

वार्षिक प्रगति आख्या 2022-23

वर्ष 2022–2023 के दौरान सम्पन्न

वार्षिक गतिविधियों का प्रतिवेदन



“ग्रास”

ग्रामीण समाज कल्याण समिति

तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा

फोन नं० (05962) 297418

ई-मेल- almora.grass@gmail.com

वार्षिक प्रगति आख्या (2022–23) अनुक्रमाणिका

क्रम०	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	अनुक्रमाणिका	I
2.	आभार	II
3.	उद्देश्य	III
4.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति	1
5.	चाइल्डलाइन इण्डिया फाउण्डेशन	2–5
6.	सनराइज़ एकेडमी, बज्वाड़	6–7
7.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना	8–13

आभार

वार्षिक प्रगति आख्या को तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़े संकलन में परियोजना क्षेत्र के संदर्भित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय एवं ग्रास संस्था के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा साधारण सभा के महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से **कार्यालय सहायक फातमा सुल्ताना अन्सारी** द्वारा इस रिपोर्ट को पूर्ण किया जा सका।



हम आभारी हैं तकनीकी संस्था “ग्रामीण समाज कल्याण समिति” (ग्रास) अल्मोड़ा के लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के परियोजना प्रबन्धक श्री गिरीश चन्द्र जोशी तथा समस्त कर्मचारी, चाइल्ड लाइन 1098, चौखुटिया के समन्वयक श्री कैलाश सिंह एवं समस्त टीम मेम्बर, सनराइज़ एकेडमी के बज्वाड़, (खेर्दा) की प्रधानाचार्या श्रीमति जया पंत एवं शिक्षिकाओं तथा नाबार्ड के अन्तर्गत कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी महानुभावों के योगदान से इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यक्रमों को निष्पादन के उपरान्त वार्षिक प्रगति आख्या को पूर्ण किया जा सका।

धन्यवाद।

(गोपाल सिंह चौहान)

अध्यक्ष

दिनांक: 29.05.2023

स्थान : अल्मोड़ा।

ग्रामीण समाज कल्याण समिति, “ग्रास”
तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा।

उद्देश्य

इस वार्षिक प्रगति आख्या को बनाने एवं तैयार करने का मुख्य उद्देश्य संस्था ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) की विभिन्न परियोजना क्षेत्रों (चाल्डलाइन 1098-चौखुटिया) (सनराइज एकेडमी-बजवाड़) (लक्ष्यगत हस्तक्षेप-अल्मोड़ा) में वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यों का विवरण एवं आंकलन करना है। इस प्रकार उनका सर्वेक्षण कर परियोजनाओं की सफलता को किस प्रकार और अधिक बेहतर किया जा सके। साथ ही आगामी वर्ष में परियोजना गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके। वार्षिक प्रगति आख्या का अवलोकन कर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की बेहतरी हेतु रणनीति बनायी जा सके।

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास)

ग्रामीण समाज कल्याण समिति गैर सरकारी सामाजिक विकास संगठन है, जिसे लोकप्रिय रूप से (ग्रास) के रूप में जाना जाता है और उत्तराखण्ड में अधिकतर गरीब समुदायों के बीच आधारित विकासात्मक हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने के लिये संस्थाध्यक्ष श्री गोपाल सिंह चौहान द्वारा इसे 1996 में स्थापित किया गया है। ग्रास उत्तराखण्ड के तीन जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में स्थानीय समुदायों के सतत् विकास के विचार के साथ वैज्ञानिक तरीके से संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और हर तरह के लोगों के साथ काम करने का प्रयास कर रहा है। इसमें 1420 एसएचजी/डब्ल्यूएसएचजी/पीजी/वीपीजी के साथ 700 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है और ग्रामीण समुदाय की सेवा कर रहे हैं। विशेष रूप से समाज से वंचित, गैर-सेवित और कमजोर वर्गों में लगभग 15,000 से अधिक परिवार शामिल हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों, युवाओं और भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसान के परिवारों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। पिछले 22 वर्षों से संगठन स्थानीय समुदाय के समर्थन से एकीकृत ग्रामीण विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण आबादी के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सुरक्षित प्राथमिक शिक्षा, प्रजनन पेयजल का प्रविधान, और बाल स्वास्थ्य और अधिकार, युवा भी शामिल हैं। हिमालयी क्षेत्र के लिये महिला सशक्तिकरण, लिंग संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, जैविक खेती, सूक्ष्म कण और सूक्ष्म उद्यम, कौशल प्रशिक्षण और विकास तथा आजीविका सुधार कार्यक्रम आदि संस्था द्वारा संचालित किये जाते हैं।



अपनी स्थापना के बाद से Grass ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किशोरियों की शिक्षा और SHG, किसान क्लब, आय सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों और महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने व समुदाय आधारित संगठनों के समग्र सामाजिक विकास में उल्लेखनीय ध्यान दिया गया है। कठिन परिश्रम द्वारा स्थानीय समुदायों की आजीविका वृद्धि के लिये कार्य करने का दृष्टिकोण रहा है। वर्तमान में ग्रामीण समाज कल्याण समिति द्वारा 03 परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

क्रम	प्रोजेक्ट	स्थान	समय	फण्डिंग एजेंसी
1	चाइल्ड हेल्प लाइन 1098	चौखुटिया	अप्रैल 2016 से	चाइल्डलाइन इण्डिया फाउण्डेशन
2	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना (TI)	तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा	अप्रैल 2010	उत्तराखण्ड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (USACS)
3	सनराइज एकेडमी बजवाड़	बजवाड़, अल्मोड़ा	01 मई 2001	ग्रास, अल्मोड़ा



चाइल्डलाइन1098

1 अप्रैल 2016 को चाइल्डलाइन फाउण्डेशन मुम्बई एवं ग्रामीण समाज कल्याण समिति, तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा द्वारा विकासखण्ड चौखुटिया में एक स बसेन्टर चलाने हेतु अनुबन्ध किया गया है।

वर्ष 2022-23 में 164 (केस) केस सब-सेन्टर में आए जिनमें शिक्षा, अनाथ, गरीबी, एड्स, दुर्व्यवहार आदि से प्रताड़ित बच्चे जो परेशान थे उनकी समस्याओं का समाधान किया गया तथा सभी को जागरूक करने के लिये विभिन्न संस्थानों में मीटिंग्स का आयोजन किया गया एवं बच्चों तथा उनके अभिभावकों को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।



चाइल्डलाइन टीम हेड-कैलाश चन्द्र जोशी व मेम्बर्स-फातमा अन्सारी, मीनाक्षी, रेखा बिष्ट, रवि बिष्ट द्वारा 31 दिसम्बर 2022 में त्याग पत्र देने के कारण नीमा कैड़ा को 01-01-2023 से टीम मेम्बर के पद पर नियुक्त किया गया इन सदस्यों द्वारा विद्यालयों, आँगनबाड़ियों, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम पंचायतों में की गई मीटिंग्स की सूची निम्न प्रकार है।



ग्राम पंचायत, SHG, आँगनबाड़ी और विद्यालयों की मीटिंग्स

क्रम	माह	केस	संबंध	ग्राम पंचायत	SHG	आँगनबाड़ी	विद्यालय			
							प्राथमिक	माध्यमिक	इण्टर कालेज	प्राइवेट स्कूल
1	अप्रैल	15	शिक्षा-15	20	16	12	11	03	02	00
2	मई	15	शिक्षा-15	19	18	11	12	02	00	02
3	जून	14	स्पानसरशिप -04 शिक्षा-10	23	18	12	00	00	00	00
4	जुलाई	16	शिक्षा-16	20	17	13	12	02	01	01
5	अगस्त	23	शिक्षा-23	20	17	14	14	02	00	02
6	सितम्बर	08	राशन-08	20	19	13	13	02	00	00
7	अक्टूबर	09	स्पानसरशिप. -01 विकलांग-08	22	20	15	15	03	00	00
8	नवम्बर	12	गली-गलौच-01 खेल संबंधी-11	20	17	15	12	01	00	01
9	दिसम्बर	13	स्पानसरशिप-11 विकलांग-02	20	16	12	12	03	00	00
10	जनवरी	04	स्पानसरशिप-01 राशन-03	20	18	14	09	02	01	03
11	फरवरी	17	राशन-17	19	17	13	11	03	00	00
12	मार्च	18	गली-गलौच-03 राशन-15	20	18	14	07	04	03	04
12		164		243	211	158	128	27	07	13

(शिक्षा-90, स्पानसरशिप-06 राशन-43, गली-गलौच-04, खेल संबंधी-11, विकलांग-10) 164 केस



चाइल्डलाइन परियोजना के अन्तर्गत चौखुटिया विकास खण्ड में चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा चौखुटिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों में आउटरीच एवं ओपन हाउस के माध्यम से सभाओं का आयोजन कर 1098 की जानकारी मुहैया कराई जा रही है तथा विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इंटर के विद्यालयों तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में परियोजना की जानकारी टीम द्वारा दी जा रही है।



चाइल्डलाइन टीम द्वारा जनता को बच्चों के प्रति जागरूक करने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें 14 नवम्बर 2022 से 21 नवम्बर 2022 तक ***"Childline Se Dosti Week"*** "12 जून 2022 से 18 जून 2022" तक एक प्रोग्राम जिसे **"Child Labour Day"** बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।

चाइल्ड लाइन दोस्ती प्रोग्राम **14 से 21 नवम्बर 2022**

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह एक अभियान है। जा कि 14 से 20 नवम्बर तक मनाया जाता है जिसका उद्देश्य चाइल्डलाइन के लाखों दोस्त बनाना है, इस अभियान में हम विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का आयोजन करते हैं जहाँ बच्चे अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने के लिये बात-चीत करते हैं। यदि आप बच्चों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे सुरक्षित रूप से विकसित हों तो दोस्ती का संकल्प लें और चाइल्डलाइन दोस्त बनें।



क्र०स०	दिनांक	आंगनवाड़ी / स्कूल	बच्चों की संख्या
1	15 / 11 / 2022	लक्ष्मी नारायण पब्लिक स्कूल (भटकोट)	60
2	16 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (बसभीड़ा)	09
3	16 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (महाकालेश्वर)	06
4	16 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (पान)	13
5	17 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (भटकोट)	06
6	18 / 11 / 2022	आंगनवाड़ी केन्द्र (उडलीखान)	03
7	18 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (उडलीखान)	11
8	18 / 11 / 2022	राजकीय जूनियर हाईस्कूल (उडलीखान)	09
9	19 / 11 / 2022	आंगनवाड़ी केन्द्र (जेतुवा)	08
10	19 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (डोंग)	08
11	19 / 11 / 2022	राजकीय जूनियर हाईस्कूल (डोंग)	08
12	21 / 11 / 2022	आंगनवाड़ी केन्द्र (सुनगढी)	06
13	21 / 11 / 2022	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (सुनगढी)	15
14	21 / 11 / 2022	राजकीय जूनियर हाईस्कूल (नागाड)	48



ग्राम प्रधान व गाँव वासियों तथा प्रधानाध्यापक, शिक्षकों तथा बच्चों को 1098 परियोजना की जानकारी पॉम्पलेट व मौखिक रूप में दी गयी उन्हें बताया गया कि चाइल्ड लाइन देखरेख एवं संरक्षण



के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटों के लिए मुफ्त एमरजेन्सी फोन आउटरीच सेवा है। टीम द्वारा इन कार्यक्रमों में बच्चों तथा बड़ों सभी को बाल अधिकारों तथा बाल विकास व बच्चों के हित सम्बन्धी कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। पूरे सप्ताह तक प्रोग्राम का आयोजन करके विभिन्न प्राथमिक, माध्यमिक, इण्टरमीडिएट स्कूलों व ऑगनबाड़ियों में

अलग-अलग ड्राइंग व पेन्टिंग एवं निबन्ध लेखन प्रतियांगिताएं कराकर बच्चों को पुरस्कार आदि वितरण करके उत्साहित किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि कभी भी आपके आस-पड़ोस या जान पहचान वाले लोगों का बच्चा परेशानी, आफत, झगड़े, में दिखे या फिर बच्चा किसी अनजान या संदिग्ध लोगों से बातचीत करता हुआ दिखे तो तुरन्त जागरूकता का परिचय देते हुए उस बच्चे का सहयोग करें, उससे पूछें कि वह किसी परेशानी में तो नहीं है या जिससे वह बात कर रहा है वो उसे किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहते। अपने आस-पास के लोगों को अपने पड़ोसी बच्चों को सुरक्षित रखने की अपील की गई तथा चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को स्कूल बैग, कापियां, रजिस्टर आदि भी वितरित किये गये।

“12 जून 2022 से 18 जून 2022” “Child Labour Day”

एक बच्चे के जीवन में से एक 14 नवम्बर बाल पूरी तरह तैयार रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण गरीब परिवारों के श्रम करना पड़ रहा है। समाप्त करने की सारी लगी।



सबसे महत्वपूर्ण दिनों में दिवस मनाने के लिये बच्चे बढी हुई आर्थिक असुरक्षा, और घरेलू आय में कमी बच्चों को मजबूरी में बाल जिससे बाल श्रम को कोशिशें कमजोर पड़ने

ग्राम पंचायतों में बाल श्रम दिवस की बैठकें

दिनांक	ग्राम पंचायत	कुल बच्चे
12 / 6 / 2022	ढांग	24
13 / 6 / 2022	महतगाँव	22
16 / 6 / 2022	सोनगाँव	28
17 / 6 / 2022	खातानागाड़	20
18 / 6 / 2022	पीपलधार	25



ग्राम पंचायतों, स्कूल आदि में मीटिंग करवाकर चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को बाल श्रम के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया—

- अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
- मनरेगा 2005 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार (अकुशल मजदूरों हेतु के साथ-साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।



अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक साबित हो रही है।

- बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये बने होते हैं कार्यस्थलों में कार्य करने के लिये नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है और गरीबी को पीढ़ीगत बनाती है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।
- बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है एवं गरीबी के पीढ़ीगत बनाता है।

- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा बाल श्रम शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुँच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय



सनराइज एकेडमी, ग्राम बजवाड़ विकास खण्ड लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा

ग्रामीण समाज कल्याण पांचवी कक्षा तक वर्ष 01 मई खण्ड लमगड़ा में सनराइज बजवाड़ में जिला शिक्षा अल्मोड़ा द्वारा मान्यता प्राप्त जा रहा है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र जीवनयापन करने वाले परिवार सनराइज एकेडमी बजवाड़ में अध्ययनरत रहे जिनमें RTE के अध्यापिकाएं— 1. जया पंत सुल्ताना अन्सारी कार्यरत थीं। कोरोना काल से ही अभिभावकों द्वारा शिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है।

SUNRISE ACADEMY BAJWAR

झंडा रोहण



समिति (ग्रास) द्वारा नर्सरी से 2001 से ग्रामीण क्षेत्र में विकास एकेडमी के नाम से ग्राम अधिकारी (बेसिक) जिला विद्यालय का संचालन किया के पिछड़े गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे अध्ययन करते हैं।

वर्ष 2022-23 में कुल 35 बच्चे 05 बच्चे थे तथा 03

2. अनीता पंत 3. फातमा

प्रत्येक कक्षा की अर्द्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर-नवम्बर माह तथा वार्षिक परीक्षाएं भी मार्च में कराई गई हैं। वर्षभर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित कराये गये हैं।

1. 15 अगस्त में प्रेम सिंह मेर द्वारा झंडा रोहण किया गया जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहे थे अब रिटायर हो चुके हैं।



2. 21 सितम्बर को संकुल में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं जैसे – 200मी0, 100मी0 तथा 50मी0 की दौड़ जिसमें 100 मी0 की दौड़ में गौरव ने द्वितीय स्थान



पुरुस्कार वितरण

तथा 50 मी0 की दौड़ में अक्षित सांगा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंताक्षरी प्रतियोगिता में गौरव, गौतम, अक्षित सांगा, दिया प्रतिभाग किया और द्वितीय स्थान

अधिकारी तथा दिव्यांजली आदि ने प्राप्त किया।

3. 14 अक्टूबर को कृमि दिवस बच्चों को एलबेंडाजोल की



कृमि दिवस

मनाया गया जिसमें स्कूल के सभी गोलियां खिलाई गईं।

4. 14 नवम्बर को बाल दिवस कविता तथा निबन्ध प्रतियोगिता में ने भाषण तथा कविता में प्रथम अंग्रेजी में भाषण देकर प्रथम स्थान

मनाया गया जिसमें बच्चों ने भाषण, भाग लिया जिसमें दिया अधिकारी स्थान प्राप्त किया। अक्षित सांगा ने प्राप्त किया।



RTE के अन्तर्गत प्री० प्राइमरी से कक्षा ०५ तक केवल ०५ बच्चे हैं।

1. अंशुमन – कक्षा ०२
2. गुंजन – के०जी०
3. कोमल – के०जी०
4. संकल्प – के०जी०
5. भाविका – नर्सरी

सनराइज एकेडमी बजवाड़-लमगड़ा

क्रम	कक्षा	छात्र			सामान्य			एससी/एस टी			ओ०बी०सी			योग
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	
1	5	8	3	11	2	3	5	4	-	4	2	-	2	11
2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	3	4	7	1	3	4	2	-	2	-	1	1	7
4	2	3	2	5	3	2	5	-	-	-	-	-	-	5
5	1	3	-	3	2	-	2	1		1	-	-	-	1
	KG/NS	3	6	9	2	3	5	1	3	4	-	-	-	9
योग	Total-35	20	16	35	13	16	29	8	1	9	3	2	5	35
	Students													

2021 में स्कूल की मान्यता मार्च में समाप्त हो जाने के कारण मान्यता की ऑनलाइन प्रक्रिया मार्च माह में की गई है जो सत्यापन के लिये ब्लॉक भेजी गई थीं जिनमें कुछ कमियां पाई गई हैं जिन्हें दूर करके प्रपत्र पूर्ण कर दुबारा सत्यापन के लिये भेजा जायेगा।



लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के सहयोग से संस्था द्वारा जनपद अल्मोड़ा के बाहरी क्षेत्रों की FSW पर आधारित कार्यक्रम लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना को वर्ष 2010 से चलाया जा रहा है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना का मुख्य उद्देश्य HIV/AIDS के प्रसार को रोकना है तथा शरीर को यौन रोगों से सुरक्षित करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं को जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न चार विन्दुओं में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है—

1. असुरक्षित यौन संपर्क से।
2. संक्रमित रक्त एवं ब्लड प्रोडक्ट (रक्त उत्पाद) से।
3. संक्रमित सुइयों, सीरिंजों, या नुकीले औजारों से।
4. HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चों को।

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के घटक

- 1- बिहेवियर चेन्ज कम्यूनिकेशन
- 2- कन्डोम प्रमोशन
- 3- STI मैनेजमेन्ट
- 4- इनेब्लिंग एन्वायरमेन्ट
- 5- कम्युनिटी मोबिलाइजेशन
- 6- रीफरल एण्ड लिंकेज

TI NGO Profile

Working Area and District	Almora
TI Working Since	2010
Typology	FSW / MIGRANTS
Target as per contract 2022-23 1) FSW 2) MIGRANTS	250 5000
Active Population as on 31 March 2023	273
Name of PD	Mr. Gopal Singh Chauhan
Name of PM	Mr. Girish Chandra Joshi
No. of Site	4
No. of Hot Spot	10
No. of PP	01
Other	0



List Of TI Staff 2022-23

S. No	Name of Staff/ PE	Designation	Qualification	Experience	Date of Joining	Date of Leaving	Phone Number	Remarks
1	Mr. Gopal Singh Chauhan	Project Director	B.Com, MBA	5 Year	22/12/2018	-	8006013556	
2	Girish Chandra Joshi	Project Manager	B.Com, MBA	5 Year	22/12/2018	-	8006013556	
3	Deepa Sirari	Counselor	MA Sociology	2 Year	01/04/2021	-	9456107392	
4	Lalit Mohan	M&E Cum Accountant	M.Com	2 Year	05/03/2022	--	6397041570	
5	Geeta Arya	ORW (FSW)	Intermediate	2 Year	01/04/2022		9548480171	
6	Shabeena	PE-1 (FSW)	Middle	9 Year	01/04/2012	-	8476834684	
7	Meena Joshi	PE-2 (FSW)	Graduation	1 Year	01/07/2021	31/5/2022	9456158367	
8	Sangeeta Devi	PE-2 (FSW)	Middle	2 Year	01/12/2020	-	7455985594	
9	Nazma	PE-3 (FSW)	Middle	3 Year	01/06/2022	-	7455985594	
10	Champa Joshi	PE-4 (FSW)	Graduation	1 Year	01/07/2021	31/5/2022	7078807051	
11	Farah	PE-4 (FSW)	Intermediate	2 Year	01/06/2022		9997698527	
12	Beena Dalakoti	ORW-1 (Migrant)	Graduation	3 Year	26/07/2022	30/9/2022	7465088289	
13	Hema	ORW-2 (Migrant)	Graduation	1 Year	26/07/2022	15/9/2022	6398366275	
14	Santosh Rawat	ORW-1 (Migrant)	12 th	1 Year	16/9/2022		7900689250	
13	Madan Mohan	ORW-2 (Migrant)	Graduation	1 Year	1/10/2022	28/2/2023	7454959626	
14	Harish Chandra Pathak	ORW-2 (Migrant)	Graduation	5 year	1/3/2023		9456743178	

Clinical Data for (April 2022 to March 2023)

SL.No	Data	Achievement
1	Clinic Visit	991
2	RMC	913
3	HIV testing	508
4	VDRL	509
5	STI	40
6	Follow-up STI cases	40
7	PT	38
8	Counselling	1065



FSW Typology Status (Clinic Visit and Counseling)

FY	Active Population	Clinic Visit	Counseling
		Total Clinic Visit	Total Counseling
2022-23 (April 2022 to March 2023)	283	991	1065

HIV OR VDRL Testing Data (April 2022 to March 2023)

Target 250

HIV Test	VDRL Test
508	509

DOTS Refer (April 2022 to March 2023)

DOTS Screening	DOTS Refer	DOTS Treatment	DOTS Reactive
1042	02	0	0

Condom Data (April 2022 to March 2023)

Condom Demand	Free Condom Distribution	SMC Condom Distribution	Outlet	Total Distribution
61625	56640	2895	491	60026

Advocacy and stakeholders Meeting

Indicator	(April 2022 to March 2023)
No. of crises Meeting	4
No. of Stake holders	11
Attendances in meeting	52
No. of advocacy meeting	12
Attendances in meeting	64
Departments covered in meetings	4
Subjects/Key issues	HIV/AIDS Co-ordination
Major outcome of meetings	Co-ordination and support from different dept.



Migrant Project Details (25 July 2022 to March 2023)

S. No	Indicator		Achievement
1	Counselling		1895
2	New Registration		5135
3	Clinical Visit		1
4	RMC		1
5	PT		1
6	STI		0
7	Follow-up		10
8	HIV Refer		777
9	HIV Testing	ICTC	1
		Camp	489
		Field	288
10	VDRL Refer		1
11	VDRL Testing		1
12	Camp		120
13	Camp Attendance		3517
14	Group Meeting (GD)		30
15	Group Meeting (GD) Attendance		845
16	Condom Demo Redemo		140 Piece
17	Social Marketing Condom (CSM)		1926 Piece
18	DOTS/TB Screening		3819

Best Practices

- ❖ Awareness of HIV/AIDS and different govt. schemes is being provided to HRG's through meetings, community events, demand generation activities etc.
- ❖ PEs does regular RMC/HIV/VDRL test of HRGs which are at a long distance of 5-8 Km's from ICTC Centre.
- ❖ Awareness of HIV/AIDS and different govt. schemes is being provided to HRGs & Migrants through meetings, community events, demand generation activities, Nukkad Natak, Mid media activities etc.
- ❖ Sells sparsh sanitary pads in field (Sanitary Pad Yojna).
- ❖ E-SHRAM & Voter ID cards for HRG's & Migrants.



Activities Pics



Migrant Camp & CBS Testing pics



3RD Community Advisory Board (CAB) pics





ग्रामीण समाज कल्याण समिति
(ग्रामस)

2024

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रगति आख्या (2023–24) अनुक्रमाणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	अनुक्रमाणिका	I
2.	आभार	II
3.	उद्देश्य	III
4.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास)	1
5.	आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (LEDP)	2–4
6.	सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (MEDP)	5
7.	दोसाद जलागम	6–8
8.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	9–10
9.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना	11–13
10.	चाइल्डलाइन 1098	14–15

आभार

वार्षिक प्रगति आख्या को तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़े संकलन में परियोजना क्षेत्र के संदर्भित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय एवं ग्रास संस्था के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा साधारण सभा के महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से **कार्यालय सहायक सरिता किरौला** द्वारा इस रिपोर्ट को पूर्ण किया जा सका।



हम आभारी हैं तकनीकी संस्था “ग्रामीण समाज कल्याण समिति” (ग्रास) अल्मोड़ा के निदेशक श्री भूपेन्द्र चौहान, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के परियोजना प्रबन्धक श्री गिरीश चन्द्र जोशी तथा समस्त कर्मचारी, चाइल्ड लाइन 1098, चौखुटिया के समन्वयक श्री कैलाश सिंह एवं समस्त टीम मेम्बर, तथा नाबार्ड के अन्तर्गत कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी महानुभावों के योगदान से इस वित्तीय वर्ष 2023–24 के कार्यक्रमों को निष्पादन के उपरान्त वार्षिक प्रगति आख्या को पूर्ण किया जा सका।

धन्यवाद।

दिनांक: 11.05.2024
स्थान : अल्मोड़ा।

(गोपाल सिंह चौहान)
अध्यक्ष
ग्रामीण समाज कल्याण समिति,
“ग्रास”
तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा।

उद्देश्य

इस वार्षिक प्रगति आख्या को बनाने एवं तैयार करने का मुख्य उद्देश्य संस्था ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) की विभिन्न परियोजना क्षेत्रों (आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (दोसाद जलागम) (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) (चाल्डलाइन 1098—चौखुटिया) (लक्ष्यगत हस्तक्षेप—अल्मोड़ा) में वित्तीय वर्ष 2023—24 में किये गये कार्यों का विवरण एवं आंकलन करना है। इस प्रकार उनका सर्वेक्षण कर परियोजनाओं की सफलता को किस प्रकार और अधिक बेहतर किया जा सके। साथ ही आगामी वर्ष में परियोजना गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके। वार्षिक प्रगति आख्या का अवलोकन कर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की बेहतरी हेतु रणनीति बनायी जा सके।

(भूपेन्द्र चौहान)

निदेशक

ग्रामीण समाज कल्याण समिति,

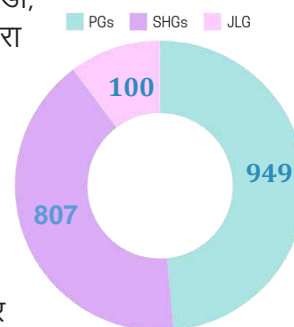
“ग्रास”

तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा।

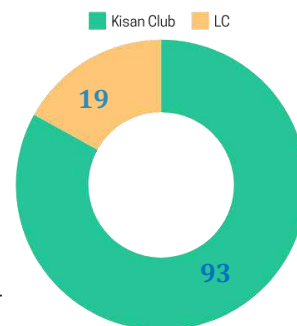
ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास)

ग्रामीण समाज कल्याण समिति जिसे ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1996 में अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह चौहान द्वारा उत्तराखंड में गरीब समुदायों के बीच अधिकार-आधारित विकासात्मक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने एवं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में की गई है।

1996 में अपनी स्थापना के बाद से, ग्रास उत्तराखंड के तीन जिलों— अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में संचालित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। संस्था ने 949 उत्पादक समूहों, 807 स्वयं सहायता समूहों, 100 संयुक्त देयता समूहों, 93 किसान क्लबों और 19 आजीविका सामूहिकों के साथ 1,192 राजस्व गांवों को शामिल किया है। समाज के वंचित, असेवित और कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संगठन 38,935 से अधिक ग्रामीण परिवारों को सेवा प्रदान करता है। ग्रास सतत विकास, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और सभी गतिविधियों में समुदाय को शामिल करने पर जोर देता है।



मुख्य रूप से भूमिहीन श्रमिक और सीमांत किसान परिवारों की महिलाओं, बच्चों, युवाओं और विकलांग लोगों पर ध्यान केंद्रित है। पिछले 27 वर्षों में, संगठन ने स्थानीय समुदाय के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास गतिविधियों को लागू किया है। इन गतिविधियों में सुरक्षित पेयजल, प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण, लिंग संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, जैविक खेती, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म उद्यम, कौशल प्रशिक्षण और विकास और आजीविका सुधार प्रदान करना शामिल है।



अपनी स्थापना के बाद से, ग्रास ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किशोर लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है। संस्था का ध्यान उत्पादक समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब, आय सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे समुदाय-आधारित संगठनों के समग्र सामाजिक विकास और महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने पर रहा है। स्थानीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि हमारा प्रमुख दृष्टिकोण है।

हम आपको ग्रास के साथ हाथ मिलाने और उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। आपका योगदान उत्तराखंड के हजारों वंचित परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ग्रास के साथ खड़े रहें और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने में हमारी मदद करें। वर्तमान में ग्रामीण समाज कल्याण समिति द्वारा 06 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।



आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (LEDP)

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित दो वर्षीय आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण महिला किसानों को मोटे अनाज की खेती और विपणन के बारे में सिखाने पर केंद्रित था। प्रशिक्षण के पहले दस दिन रौन-डाल और धामस में आयोजित किए गए और इसमें मुख्य वर्षा आधारित फसलों जैसे मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, कौणी, लाल धान, दालें, गहत, काले भट्ट आदि के उत्पादन को शामिल किया गया। पूरे प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोडा, कृषि विज्ञान केंद्र मटेला, कृषि विभाग, जैविक बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक, जिला उद्योग केंद्र, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और संसाधन सहकारी समिति के विशेषज्ञ शामिल थे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की किसान महिलाओं की आजीविका और उद्यमशीलता उद्यम को बढ़ाने के लिए था।



प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्, महिला किसानों ने अपने खेतों में मंडुवा, झंगोरा, लाल धान, चौलाई, काले भट्ट और गहत जैसी विभिन्न फसलों की खेती तकनीकी ज्ञान एवं जानकारी द्वारा की। इसके अतिरिक्त, इन किसानों ने काले भट्ट और सोयाबीन से दूध निकालकर घर पर पनीर (टोफू) बनाना भी सीखा। पहले महिलाएं मंडुवा 10 से 18 रुपये प्रति किलो बेचती थीं, लेकिन इस साल उन्होंने 40 रुपये प्रति किलो मंडुवा बेचा, जिससे इन महिला किसानों के आय में वृद्धि हुई एवं मुनाफे में 122 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।



ग्रास संस्था ने इन सभी महिला किसानों का मृदा परीक्षण की जाँच भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विभाग, हवालबाग में कराया। जिसके प्रमाण पत्र महिला किसानों को वितरित कर मृदा परीक्षण विशेषज्ञों ने किसानों को उनके मृदा परीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर उनके खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने की सलाह दी। किसानों को जैविक खेती के लिए वर्मीकम्पोस्ट जैसे उर्वरकों और जैविक दवाओं के उपयोग की भी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,



पीएच, सल्फर, मैंगनीज, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।



आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत, रौन डाल एवं धामस के 60 किसानों को हवालबाग क्षेत्र में प्रगति आजीविका स्वायत्त सहकारिता के मंडुवा बेकरी यूनिट में महिला किसानों को एक दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर ले जाया गया। भ्रमण के दौरान बेकरी इकाई के कुशल मास्टर प्रशिक्षकों ने मंडुवा उत्पादों में मूल्य संवर्धन के तरीकों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, विकास आजीविका स्वायत्त सहकारिता के कारीगरों ने बेर, संतरा, माल्टा, नींबू का रस, आम, मिर्च, लहसुन, आवला अचार, हर्बल चाय और काढ़ा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन के बारे में जानकारी प्रदान की।

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की यांत्रिक प्रयोगशाला में महिलाओं के कार्यभार को कम करने वाली कृषि से संबंधित मशीनें जैसे मंडुवा थ्रेशर एवं परलर, झंगोरा सफाई मशीन, धान थ्रेशर, पंक्ति विधि मशीन, दरांती, कुदाल एवं पंजा का प्रदर्शन किया गया। मैकेनिक इंजीनियर ने मशीनों के उपयोग की विधि का प्रदर्शन किया, जिसे महिलाओं ने खूब सराहा गया।



ग्रास संस्था द्वारा 150 महिला किसानों के लिए 2 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें खेत की तैयारी, मोटे अनाज के लिए बीज पंक्ति विधि और मिट्टी परीक्षण के बाद उर्वरकों के उचित उपयोग जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के डॉ. दिनेश जोशी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक योगेश पंचपाल के द्वारा भी किसानों को जानकारी दी गयी।





महिला किसानों को मोटे अनाज की खेती और विपणन से उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए, संस्था द्वारा एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गयी। यहां महिलाएं अपना मंडुवा इकट्ठा कर सकती हैं, उसे मंडुवा थ्रेशर से साफ कर सकती हैं और झंगोरा जैसे अन्य उत्पादों के साथ पैक करके बेच सकती हैं। प्रदर्शन इकाई ग्रास संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित है। ग्रास संस्था द्वारा इस प्रदर्शन इकाई में निम्नलिखित उपकरण रखे गए हैं:-

क्र० सं०	यंत्र	संख्या
1	विवेक मंडुवा थ्रेशर कम पर्लर	1
2	इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन क्षमता 3 क्विंटल	1
3	पैकेजिंग मशीन	1
4	छलनी	2
5	सूपा	2
6	परखी	4
7	पैकेजिंग पोलोथीन	5



सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (MEDP)

ग्रास संस्था ने नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 तक 15 दिवसीय जूट बैग निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण के बाद विभिन्न महिला समूहों की सदस्यों ने बैग, पर्स, वाटर बैग और अन्य जूट आधारित सामान बनाना शुरू किया। वे बोतल शॉपिंग बैग का उत्पादन और बिक्री भी कर रहे हैं। उत्पादन के लिए कच्चा माल ग्रास संस्था के महिला शोरूम, जिला पंचायत परिषद की दुकान से क्रय किया जा रहा है।



अपने व्यवसाय को सहारा देने के लिए ये उद्यमी अपने-अपने समूहों से ऋण ले रहे हैं और बैंक से सीसीएल बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। ये महिलाएं इस व्यवसाय से प्रति व्यक्ति 5,000 रु प्रति माह तक कमा रहे हैं।



दोसाद जलागम

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) तल्ला चीनाखान अल्मोडा नाबार्ड के जलागम विकास निधि के तहत दोसाद जलागम परियोजना का संचालन कर रही है। इस दोसाद जलागम परियोजना में द्वाराहाट विकास खंड के अंतर्गत 12 गांव शामिल हैं, जिनके नाम हैं बरगल, भंडरगांव, छब्बीसा, चिललगांव, मासर, मेल्टा, नहरागूँठ, सकुनी, सलिसुनौली, सतीनौगांव, स्यालसुना और उभ्याड़ी। परियोजना की प्रमुख गतिविधियों में से एक जलाशय विकास है, और क्षमता निर्माण चरण को 14 फरवरी, 2024 को मंजूरी दी गई थी।

दोसाद जलागम परियोजना का लक्ष्य मिट्टी के कटाव और वर्षा जल अपवाह की हानि को महत्वपूर्ण रूप से कम करके और भूजल पुर्नभरण में सुधार करके प्राकृतिक संसाधन आधार को बहाल करना है। परियोजना का लक्ष्य चयनित कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करना भी है। यह सुदृढ़ जलागम प्रबंधन योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए लक्षित ग्राम पंचायतों (जीपी) की क्षमता का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना भूमिहीन और कमजोर परिवारों को आय-सृजन गतिविधियों में शामिल करेगी।

ग्रामीणों को सहभागी जलागम विकास कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गांव-गांव में बैठकें आयोजित की गईं। जलागम कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं वन पंचायत सरपंच से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त की गई, साथ ही दोसाद जलागम में श्रमदान एवं सहयोग की सहमति भी प्राप्त की गई। दोसाद जलागम परियोजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 1000 हेक्टेयर है तथा वन पंचायतों की कृषि भूमि पर जल संरक्षण विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

गैर-कृषि क्षेत्रों में खेत तटबंध, चेक डैम, कच्चे गड्ढे टैंक आदि निर्माण कार्य भी किये जायेंगे। परियोजना का पहला चरण छह महीने के क्षमता-निर्माण चरण कार्यक्रम के साथ, दोसाद जलागम परियोजना के 100 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करेगा। जिसमें क्षमता निर्माण चरण कार्यक्रम छह महीने तक चलाया जाएगा।

संस्था द्वारा 4 दिवसीय श्रमदान शिविर में निम्न कार्यों को सम्पन्न किया गया—

1. ग्राम चिललगाँव में कपतोई हैण्डपम्प की सफाई
2. गाँव से हैण्डपम्प तक जाने के रास्ते की सफाई
3. कूल्लूधार हैण्डपम्प की सफाई की सफाई तथा नालो की सफाई
4. कपतोई नौला की नाली एवं झाड़ियो की सफाईग्राम मासर अनु0 जाति क्षेत्र मे ढोली नौले की नाली, नौले, झाड़ियो की सफाई
5. मासर मे नौलो की सफाई
6. ग्राम सभा छब्बीसा के मल्ला नौला की नाली, नाली, झाड़ियो की सफाई की गई







जलागम समुदाय के लोगो को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। शैक्षिक भ्रमण के अर्न्तगत मासर से जलागम क्षेत्र धौलादेवी विकास खण्ड मे धसपड़ ग्राम जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। 20 सदस्यो को प्रत्येक वनपंचायत के सरपंच, ग्राम प्रधान, ग्राम वासियो को दिनांक 15.03.2024 को भ्रमण कराया गया। श्रीमती माधवी महारा पूर्व जलागम फेसिली टेटर द्वारा ग्राम में कन्दूर पिट, सोखता पिट, फलदार वृक्ष, वन पंचायतो में वृक्षारोपण, सोलर टैंक एवं पम्प, एल0डी0पी0 टैंक मलचिग खेती वर्मी कम्पोस्ट, पॉली हाउस, बकरी बाड़ा पशुपालन आदि के कार्यक्रम सदस्यो को प्रदर्शित किया गया।



शैक्षिक भ्रमण के पश्चात् जलागम गाँव मे जलागम समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक गाँव समिति के प्रतिनिधियों को एकद्रीय ग्राम जलागम समिति का VWC गठन किया जायेगा। PIA और VWC सदस्य CBP के अपेक्षित ट्रीटमेंट कार्यों के बारे में योजना तैयार करेगे। VWC में जलागम के लोगो द्वारा चुने गए कम से कम 9 सदस्य होंगे जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों व समूहों के प्रतिनिधित्व के साथ 30% महिला सदस्य होगी।



राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता विकास प्रशिक्षण निदेशालय, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड के सहयोग से विकासखण्ड भैसियाछाना जिला अल्मोड़ा के न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका शुभारंभ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और रेखीय विभागों के कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री भूपेन्द्र चौहान द्वारा सतत् विकास लक्ष्य पर चर्चा करते हुए 17 लक्ष्यों को विस्तार से प्रशिक्षण में बताया गया तथा 9 थीमों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) उद्देश्यों और संकेतकों का एक सार्वभौमिक समूह है जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015, सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में **“Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development”** के तहत सदस्य देशों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development goals) के अंतर्गत 17 विकास लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य अंगीकृत किये गए हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा भी अपनाया गया है।



राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री गोपाल सिंह चौहान, भूपेन्द्र चौहान, दीपा सिराड़ी, गिरीश चन्द्र जोशी और हरीश चन्द्र पाठक मास्टर ट्रेनर थे। इस प्रशिक्षण के दौरान, अन्य राज्यों में मॉडल ग्राम पंचायत के जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) की प्रस्तुति, 15 वें वित्त आयोग, मूल अनुदान (Untied Fund), आबद्ध अनुदान (Tied Fund), 5 वॉ राज्य वित्त आयोग, प्रस्तुति और स्याल्दे विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बरंगल की आदर्श जीपीडीपी का प्रस्तुतीकरण एवं क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी।



प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विकासखण्ड भैसियाछाना में निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया था:-

क्र० सं०	सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम प्रधानगणों की संख्या	ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या	रेखीय विभाग अधिकारियों/ कार्मिकों की संख्या	कुल प्रतिभागी
1	नैणी, देवड़ा, सल्ला, पूनाकोट, पेटशाल, डुंगरी, दशौ, दिगोली, कुंजबरगल, भेटाबड़िया	10	65	10	85
2	सिमखल्या, कुमौली, अलई, खासतिलाड़ी, चनोली, बमनतिलाड़ी, सूपई, छानी, जोग्यूडा	9	61	10	80
3	बौड़ा, धौलनैली, त्रिनैली, लिंगुणता, घुन्घोली, डुंगरलेख, बूंगा, नौगाँव, हटौला	9	64	10	83
4	पाण्डेतोली, डालाकोट, शील, कुंजरतौड़ा, मल्ली धौनी, थिकलना, नैनीगूँठ, न्योली, हरड़ा	9	59	10	78
5	सल्लाभाटकोट, सल्यूड़ी, पभ्या, नाली मल्ली, नाली तल्ली, जिंगल, कुलकिमौला, भैसियाछाना	8	56	9	73
6	पल्यू, दियारी, कौचुला, कलौन, बबुरियानायल, उटिया, बेलवालगाँव, खौकरी	8	54	9	71
कुल		53	359	58	470

क्र० सं०	विकासखण्ड	क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या	रेखीय विभाग अधिकारियों/ कार्मिकों की संख्या	कुल प्रतिभागी
1	भैसियाछाना	21	09	30
कुल		21	9	30



लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना

संस्था 2010 से उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वित्तपोषित लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अल्मोड़ा जिले में संचालित कर रही है। यह परियोजना एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने और अल्मोड़ा जिले के बाहरी क्षेत्रों में महिला यौनकर्मियों के बीच यौन संचारित रोगों से सुरक्षा पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संस्था को अपना लक्ष्य 250 से बढ़ाकर 400 करना है, जिसमें अल्मोड़ा में 250 और रानीखेत में 150 का लक्ष्य शामिल हैं। 2021-22 में, भारत के हर जिले में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना चलाने वाले संस्थाओं के माध्यम से उच्च जोखिम वाली श्रेणियों की पहचान करने और एक मानचित्र आंकलन बनाने के लिए प्रोग्रामेटिक मैपिंग और जनसंख्या आधार अनुमान (पी-एमपीएसई) गतिविधि शुरू की गई।

भारत सरकार ने नाको के लिए तीन लक्ष्य निर्धारित किए हैं (1) सभी अनुमानित पीएलएचआईवी में से 95% को अपनी एचआईवी स्थिति पता होनी चाहिए, (2) सभी पीएलएचआईवी में से 95% को एआरटी सेंटर से जोड़ा जाना चाहिए, और (3) सभी में से 95% को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। पीएलएचआईवी के वायरल लोड को कम किया जाना चाहिए।

इसके अलावा संस्था जुलाई 2022 से 5,000 प्रवासियों पर भी काम कर रही है। इस वर्ष अधिक लोगों का परीक्षण करने के लिए परियोजना में नए क्षेत्रों के चयन और समुदाय-आधारित स्क्रीनिंग पर अधिक



ध्यान दिया गया है।

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के फील्ड कर्मचारी एक-से-एक बैठक, समूह बैठकों, सामुदायिक कार्यक्रमों, वकालत, स्वास्थ्य कैप, ड्रॉप-इन सेंटर बैठकों, आईसीसी सामग्री वितरण आदि के माध्यम से एचआईवी महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक हॉट स्पॉट पर जाते हैं। महिला यौनकर्मियों को उनकी मासिक मांग के आधार पर सरकार द्वारा मुफ्त कंडोम दिए जाते हैं।

प्रवासी कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के फील्ड स्टाफ द्वारा प्रवासी मजदूरों, नेपालियों, बिहारियों तथा अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में अल्मोड़ा जिले में आने वाले सभी लोगों को संस्था में पंजीकृत किया जाता है। एचआईवी जैसी महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समूह बैठकें,

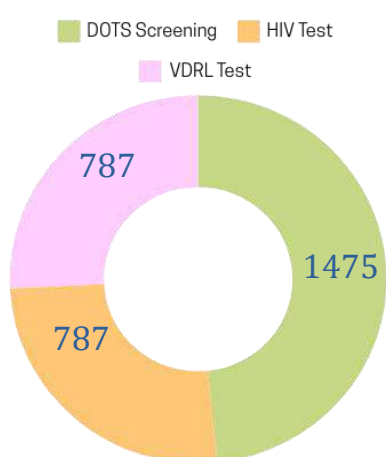


आईपीसी सामुदायिक नुक्कड़ नाटक, सभा कार्यक्रम, वकालत, स्वास्थ्य कैप, ड्रॉप-इन सेंटर बैठकें, आईसी सामग्री वितरण आदि आयोजित किए जाते हैं। एचआईवी जांच, बीपी परीक्षण और दवाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं।

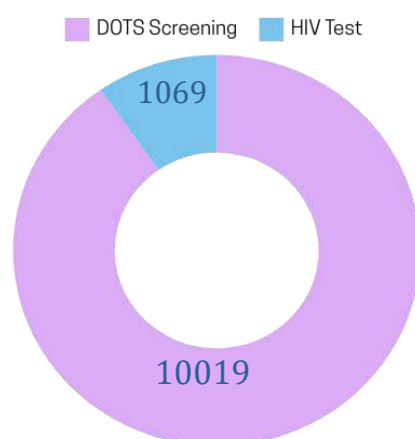
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं को जागरूकता कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न चार बिन्दुओं में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है—

1. असुरक्षित यौन संपर्क से।
2. संक्रमित रक्त एवं ब्लड प्रोडक्ट (रक्त उत्पाद) से।
3. संक्रमित सुइयों, सीरिंजों, के स्तेमाल से।
4. संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चों को।

1 दिसंबर को, जो विश्व एड्स दिवस है, लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की जाती हैं। हमारे द्वारा नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा में आयोजित विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. सी. पंत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. आर.सी. सहित नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। पंत ने एचआईवी के बारे में उपयोगी जानकारी दी।



FSW Testing



Migrant Testing



वर्ष में दो बार, आकर्षक खेलों और प्रश्न-उत्तर सत्रों के माध्यम से एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन लाभार्थियों को एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूक रहने में मदद करते हैं।

पियर, जो अक्सर समुदाय के भरोसेमंद सदस्य होते हैं, सैनिटरी पैड के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके वितरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर, सेनेटरी पैड योजना के हिस्से के रूप में, पियर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व, सैनिटरी पैड के उचित उपयोग और स्पर्श सैनिटरी पैड जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उपयोग के संभावित स्वास्थ्य लाभों के बारे में शिक्षित करते हैं। वे इन पैडों को सीधे समुदाय को भी बेचते हैं, जिससे वे उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे जिनके पास स्टोर या किफायती विकल्पों तक आसान पहुंच नहीं है।

इस प्रकार का जमीनी स्तर का दृष्टिकोण न केवल बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि मासिक धर्म के आसपास के कलंक को भी कम करता है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाता है और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है।



चाइल्डलाइन 1098

चाइल्डलाइन 1098 परियोजना एक पहल है जो भारत में सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे, टोल-फ्री आपातकालीन फोन सेवा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत पहली बार जून 1996 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) में परिवार और बाल कल्याण विभाग की एक फील्ड एक्शन परियोजना के रूप में हुई थी। यह परियोजना के प्रोफेसर जेरु बिलिमोरिया द्वारा स्थापित की गई थी, और बाद में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, एक एनजीओ बन गई।

चाइल्डलाइन 1098 अब एक राष्ट्रव्यापी हेलपलाइन है जो साल में 365 दिन संचालित होती है, जो संकट में फंसे बच्चों को मुफ्त आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। परियोजना का लक्ष्य बच्चों को उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रासंगिक सेवाओं से जोड़ना है। पिछले कुछ वर्षों में, चाइल्डलाइन 1098 एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है जिसने भारत में लाखों बच्चों की मदद की है।

चाइल्डलाइन 1098 भारत में उन बच्चों के लिए 24 घंटे की टोल-फ्री आपातकालीन फोन सेवा है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यदि आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है, तो आप चाइल्डलाइन 1098 डायल कर सकते हैं, और प्रशिक्षित पेशेवर संकट कॉल में भाग लेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। हेलपलाइन को विभिन्न प्रकार के संकटों को दूर करने और जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

“12 जून 2023 से 18 जून 2023 Child Labour Day”

एक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक 14 नवम्बर बाल दिवस मनाने के लिये बच्चे पूरी तरह तैयार रहते हैं। बड़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ रहा है। जिससे बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी।



ग्राम पंचायतों में बाल श्रम दिवस की बैठकें

दिनांक	ग्राम पंचायत	कुल बच्चे
12/6/2023	महतगाँव	20
13/6/2023	सोनगाँव	24
16/6/2023	ढांग	25
17/6/2023	पीपलधार	28
18/6/2023	खातानागाड	26

ग्राम पंचायतों, स्कूल आदि में मीटिंग करवाकर चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को बाल श्रम के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया—

- अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
- मनरेगा 2005 शिक्षा का अधिकार
- अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार (अकुशल मजदूरों हेतु के साथ-साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा बाल श्रम शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक साबित हो रही है।
- बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये बने होते हैं कार्यस्थलों में कार्य करने के लिये नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है और गरीबी को पीढ़ीगत बनाती है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।
- बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है एवं गरीबी के पीढ़ीगत बनाता है।





ANNUAL REPORT 2024-25



+91 (5962) 359585



www.grass.org.in



Talla Chinakhan, Almora (Uttarakhand)



MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Dear Friends, Supporters, and Partners,

As we reflect on the financial year 2024–25, I am proud to share the continued progress we've made in our mission to empower communities through integrated and inclusive development.

This year, our work remained rooted in three key focus areas—Health, Livelihoods, and Natural Resource Management. Through our health-based interventions, we supported vulnerable groups with access to essential services, awareness, and dignity. Our livelihoods initiatives helped rural families enhance their incomes and resilience, particularly by promoting skill development, entrepreneurship, and women's economic participation. Meanwhile, our efforts in natural resource management, particularly through watershed-based approaches, have strengthened ecological sustainability and water security across many communities.

These milestones were made possible by the commitment of our team, the active participation of our community members, and the continued support of our funding partners and collaborators. Each contribution has played a role in deepening our impact and reinforcing our belief that lasting change comes from the ground up.

As we move ahead, we reaffirm our commitment to equity, sustainability, and community-led development. We thank you for being a part of this journey.

GOPAL SINGH CHAUHAN

PRESIDENT

Table of Contents

About Us	4
LEDP	5
DOSAD	14
TI	16

Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) is a non profit organization founded in 1996 by Mr. Gopal Singh Chauhan. Headquartered in Uttarakhand, GRASS has been working for nearly three decades to empower marginalized and underserved communities, particularly in the districts of Almora, Bageshwar, and Nainital. Our work is guided by a rights-based approach and a firm belief in community-led development.

From its inception, GRASS has focused on creating sustainable and inclusive change through active participation of the local population. Our interventions span across a range of development areas including access to safe drinking water, early childhood care and education, maternal and child health, skill building, organic farming, microenterprises, and livelihoods. We place special emphasis on empowering women, youth, and persons with disabilities—helping them become active participants in their own progress.

Over the years, GRASS has facilitated the formation of self-help groups, producer groups, and collectives that enable rural families to access financial services, improve their skills, and increase income. Our efforts have also included gender sensitization, leadership development, and capacity building—helping communities identify their own needs and solutions.

Our journey is one of partnership, participation, and perseverance. GRASS continues to work hand-in-hand with local communities to build a future where rural families are healthy, self-reliant, and resilient—leading the way toward a more equitable and just society.


8,883+

Beneficiaries Trained

Good Governance, Business & Marketing Skills


905+

Beneficiaries Trained

Jute Bag & Handicraft Training


463+

Beneficiaries Trained

Panchayati Raj Training


215+

Beneficiaries Trained

Organic Farming & Certification


210+

Beneficiaries Trained

Skill Based Training

55,202+

Beneficiaries

48%

 of total beneficiaries are
Women & Girls

1,645+

Villages

950+

Producer Groups (PGs)

916+

Self Help Groups (SHGs)

167

 Joint Liability Groups
(JLGs)

Livelihood and Enterprise Development Programme

Introduction

The Livelihood and Enterprise Development Programme (LEDP), supported by NABARD and implemented by Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS), was initiated in the remote villages of Raun, Daal, and Dhamas of Hawalbagh block in Almora district. The programme aimed to empower women farmers, especially those from marginalized and economically weaker sections, by improving their income through better farming practices, enterprise promotion, and financial inclusion.

Under this programme, 150 farmers—primarily women from Scheduled Castes and low-income households—were directly supported. The focus was on enhancing their skills in agriculture, organic and climate-resilient farming, soil health, water conservation, and value-added production. Training needs were carefully identified, and targeted capacity-building sessions were conducted to strengthen their knowledge and practices.

In addition to technical training, the programme worked to improve access to credit and financial services through Self-Help Groups (SHGs), promote financial literacy, and support small-scale investments in agriculture and micro-enterprises. Women farmers received guidance in enterprise management, marketing, and record-keeping, enabling them to manage their businesses more effectively.

Continuous expert support and advisory services were provided to help participants start and sustain their livelihood activities. The programme also collaborated with resource agencies to connect farmers with essential infrastructure like processing units, storage facilities, and market linkages.

By combining skill development, financial access, infrastructure support, and community-based approaches, the LEDP made significant progress in empowering rural women, strengthening SHGs, and fostering sustainable livelihoods in the region.

Impact of the Programme

Income Growth:

Farmers saw a 60–80% rise in income. Earlier, millet sold for ₹10–20/kg; now it sells for ₹60–70/kg due to better quality.

Women's Empowerment:

Over 30 women started making and selling millet flour. Many became seed suppliers, gaining confidence and leadership in their communities.

Better Farming:

Healthier soil and improved techniques helped farmers grow more, using natural and eco-friendly methods.

Stronger Communities:

Access to credit, training, and market connections helped villages become more self-reliant. Women-led SHGs played a key role in this transformation.



10-Day Training Programme

1. Training and Capacity Building

To achieve the programme objectives, intensive 10-day capacity building programmes were organized in four batches—two in Dhamas and two in Raun-Daal—covering a total of 150 women farmers. Each batch received personalized attention and hands-on learning. A refresher course was also conducted to reinforce the learnings.

The training focused on strengthening farming practices, improving productivity, diversifying income sources, and ensuring long-term sustainability. Sessions balanced theoretical knowledge with practical demonstrations, making it easier for farmers to adopt new techniques.

Key Training Modules:

- **Sustainable Agricultural Practices:**
 - Crop rotation for maintaining soil fertility and pest control.
 - Composting for natural fertilizer production.
 - Integrated pest management to reduce pesticide dependency.
 - Soil moisture conservation using mulching and drip irrigation.
- **Organic Farming:**
 - Use of bio-fertilizers and vermicomposting.
 - Preparation of eco-friendly natural pesticides.
 - Basics of organic certification for better market value.
- **High-Yield Crops:**
 - Drought-resistant varieties of mandua (finger millet).
 - Nutritional benefits of local millets like jhangora (pearl millet) and mandua.
 - Promotion of improved varieties like VL-400, VL-379, and VL-376 of finger millet.

Objectives

- To enhance the income of women farmers through improved agricultural practices and value-added products.
- To build capacity in organic and climate-resilient farming techniques.
- To improve soil health and promote the use of efficient and sustainable farming tools.
- To strengthen financial literacy and facilitate easy access to credit through Self-Help Groups (SHGs).
- To support women farmers in processing, packaging, and marketing their produce more effectively.



10-Day Training Programme (Contd.)

- **Soil Health and Fertility Management:**
 - Soil testing for nutrient assessment.
 - Use of cover cropping and green manure to reduce chemical inputs.
- **Water Conservation Techniques:**
 - Rainwater harvesting.
 - Efficient irrigation methods like drip systems.
- **Post-Harvest Handling and Value Addition:**
 - Techniques for cleaning, grading, and packaging to fetch better prices.
 - Value-added production using millets and other local crops to increase shelf life and income.

2. Expert Involvement and Institutional Support

Training sessions were led by subject experts from reputed institutions such as:

- Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan (VPKAS)
- Krishi Vigyan Kendra (KVK)
- District Industries Centre (DIC)

Their expertise ensured scientific accuracy, field relevance, and real-time demonstrations for better farmer engagement.

3. Market Linkages and Cooperative Promotion

Marketing and branding were critical components of the training:

- Branding of millets as a “superfood” to appeal to modern and urban consumers.
- Direct-to-consumer models and access to wholesale markets were discussed.
- Formation of cooperative groups to promote resource-sharing and collective bargaining for better pricing and access to credit.

4. Government Schemes and Financial Support

Farmers were introduced to key government schemes to expand their entrepreneurial efforts:

- National Rural Livelihoods Mission (NRLM): Support for SHGs and producer groups.
- Agri-Entrepreneurship Schemes: Financial assistance for processing and marketing units.
- Startup India Initiative: Resources and mentorship for rural innovations in agriculture.

Outcomes and Impact

The 10-day training proved transformational, equipping women farmers with both technical and entrepreneurial skills to succeed in modern agriculture.

Key outcomes included:

- Improved agricultural practices: Adoption of sustainable farming methods and high-yield crops enhanced productivity and climate resilience.
- Financial literacy and empowerment: Women gained valuable knowledge in money management and business planning.
- Marketing and value addition: Farmers learned techniques to enhance the appeal of their products and create new income streams.
- Cooperative support and funding access: Understanding the benefits of collective institutions and how to tap into government assistance.



Refresher Training: Activity Overview and Outcomes

To reinforce the knowledge gained during the initial 10-day training sessions, a 2-day refresher training was conducted for all batches. The primary aim of this follow-up session was to strengthen key concepts and help farmers successfully apply new practices in their own fields.

Key Activities:

1. Review of Initial Training:

- A recap of the 10-day training was conducted, with special emphasis on the practical application of the techniques learned.

2. Reinforcement of Core Concepts:

- The training revisited critical themes such as sustainable agriculture, organic farming, high-yielding fingermillet cultivation, and efficient water management.

3. Addressing Agricultural Challenges:

- Farmers shared their on-ground issues, and expert trainers provided solutions. This helped build farmers' confidence in adopting new practices.

4. Practical Demonstrations:

Demonstrations were held on:

- Fingermillet processing
- Producing milk from soybean and black bhatt (black soybean)
- Preparing millet-based nutritious namkeen.

5. Soil Nutrient Management:

- A master trainer delivered in-depth guidance on soil health, balanced fertilizer use, and nutrient management.

6. Farmer Feedback and Participation:

- Farmers actively shared their experiences, challenges, and suggestions during open discussions, creating a participatory and responsive learning environment.

Demonstration Unit: Activity Overview and Outcomes

Initiation and Purpose

Under the LEDP initiative, Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) established a Demonstration Unit aimed at promoting sustainable practices in millet cultivation and marketing to enhance the income of rural women farmers. Funded by NABARD, this unit served 150 women farmers from the villages of Raun, Daal, and Dhamas.

The unit was formally inaugurated by District Development Manager, NABARD, Mr. Girish Chandra Pant, and a focused training session was held on improving agricultural productivity and financial returns. The event was attended by officials from the implementing organisation, including Mr. Gopal Singh Chauhan (Chairman) and Mr. Bhupendra Chauhan (Executive Director), as well as the Master Trainer and a group of women farmers. During the event, a live demonstration of the Mandua Thresher cum Pearl Millet Machine was conducted by mechanic Shiv Singh, introducing farmers to modern tools for millet processing.

Outcome

1. Strengthened Knowledge:

Farmers gained a deeper understanding of advanced agricultural practices and techniques.

2. Improved Implementation:

Field-level problems were addressed, enabling more effective application of training in real farm conditions.

3. Increased Productivity:

Better soil health and improved crop management practices led to noticeable gains in productivity.

4. Community Empowerment:

Peer learning and mentoring created a stronger support system within the farmer community.

5. Continued Support:

Post-training, farmers continued to receive technical guidance and access to relevant resources to sustain their progress.

Demonstration Unit (Contd.)

Selection of Beneficiaries

The unit specifically targeted 150 women farmers, with key participants like Mrs. Kunti Devi (from Gomti Producer Group, Raun) and Mrs. Rama Devi (from Jai Golu Group, Raun) selected for their active involvement in agriculture and openness to adopting new practices. These women played a pivotal role in peer learning, training other members, and acting as role models in replicating successful practices.

Training and Skill Development Focus

The Demonstration Unit served as a hub for hands-on training in the following areas:

1. Millet Cultivation Techniques:

Emphasis was placed on sustainable farming practices like crop rotation and water conservation to improve soil fertility and reduce dependence on chemical inputs.

2. Use of Advanced Equipment:

Women farmers were trained in the use of modern tools such as the Mandua Thresher and packaging machines, significantly improving efficiency in millet farming and processing.

3. Marketing and Branding:

The training included modules on attractive packaging, branding of millet products, and marketing strategies to fetch better prices in local markets.

4. Value Addition:

Farmers were taught how to convert millets into value-added products, expanding market opportunities and income potential.

Educational Exposure Visit: Empowering Women Farmers Through Learning and Practical Insights

Purpose and Overview

As part of the programme, an educational exposure visit was organized on 7 March 2024 for 60 women farmers from the villages of Raun-Daal and Dhamas. The aim of the visit was to enhance their understanding of value-added agricultural products, modern farming techniques, and rural entrepreneurship by observing successful enterprises and institutions in the Hawalbagh area. The visit provided farmers with first-hand experience of innovation in agriculture and food processing.

Key Highlights of the Visit

1. Mandua Bakery Unit – Pragati Livelihood Cooperative

The visit began with a tour of a millet-based bakery unit operated by Pragati Aajeevika Swayat Sahkarita, Hawalbagh. Here, women observed the production of high-quality bakery items like bread, cakes, snacks, and biscuits made from millets. Master trainers demonstrated how traditional grains like mandua can be turned into value-added products, increasing market value and income.

Results and Impacts

1. Increased Awareness and Skill Enhancement:

Farmers gained valuable knowledge in organic farming, soil health, and the use of modern equipment, leading to improved productivity and income.

2. Improved Productivity:

Adoption of advanced techniques and machinery helped reduce manual labor, increase yield, and improve post-harvest efficiency.

3. Expanded Market Access:

Training in quality control and packaging enabled farmers to enhance product quality and reach broader markets.

4. Women's Empowerment:

The tools, training, and support provided through the Demonstration Unit contributed significantly to the economic independence and social empowerment of women farmers, thereby enhancing household incomes and rural resilience.

Educational Exposure Visit (Contd.)

2. Fruit Processing Unit – Pragati Livelihood Cooperative

Farmers visited the cooperative's fruit processing unit where local fruits and herbs are used to prepare juices, pickles, and herbal teas. They learned about processing techniques, packaging standards, and marketing strategies that can significantly enhance income through value addition and proper branding.

3. Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan (VPKAS)

At this agricultural research institute, women were introduced to agricultural tools and mechanization designed to reduce labor intensity and improve productivity. Demonstrations of tools such as the mandua thresher, pearler, and row planting machines showed how simple mechanization can save time and effort while improving yield. Traditional and modern tools were shown as complementary approaches.

4. Krishi Vigyan Kendra (KVK), Matela

At KVK, Dr. Rakesh Meer conducted a session on high-yield vegetable seeds and polyhouse cultivation techniques. Farmers learned about region-suitable crops like bottle gourd, bitter melon, pumpkin, and tomato, and how polyhouse farming enables year-round production, leading to better income and resource use.

Soil Testing Initiative: Improving Fertility Through Scientific Practices

Purpose and Overview

To support better crop planning and soil management, soil samples were collected from farmers' fields in Dhamas, Raun, and Daal, and analyzed for nutrient content and soil health. The goal was to identify deficiencies and provide farmers with tailored recommendations for the use of organic fertilizers and improved fertility management.

Key Findings from Soil Testing

1. pH Levels:

The soil pH ranged from 6.20 to 7.47, indicating slightly acidic to neutral conditions, which are generally suitable for most crops. However, some samples (e.g., Vimla Devi from Raun, pH 5.65) required pH correction. Farmers were advised to use lime and other treatments to balance pH and improve nutrient uptake.

2. Electrical Conductivity (EC):

EC values ranged from 0.009 to 0.436, indicating mild to moderate salinity levels. Though within safe limits, farmers were advised to monitor irrigation practices to prevent salt build-up, which can hinder plant growth.

3. Nitrogen Deficiency:

Several samples, especially from Dhamas and Raun, showed low nitrogen levels, which can lead to yellowing of leaves and reduced yield. Farmers were recommended to use organic nitrogen sources like compost, green manure, and animal dung.

Outcomes

1. Knowledge of Value Addition:

Farmers understood how processing and packaging can increase the market potential of crops like mandua and fruits, making them more profitable.

2. Understanding Agricultural Mechanization:

Hands-on demonstrations helped farmers recognize how modern tools can improve efficiency and productivity while reducing physical workload.

3. Introduction to High-Yield Crops:

Exposure to improved seeds and protected cultivation methods inspired farmers to explore more profitable and climate-resilient farming techniques.

4. Empowerment of Women Farmers:

The visit boosted the confidence of women in adopting new ideas. It promoted entrepreneurship and opened doors to new income-generating opportunities through value-added farming.

5. Networking and Collaborative Learning:

Farmers, trainers, and agricultural experts exchanged ideas and best practices. This peer learning environment encouraged farmers to implement innovative techniques suited to their local context.

Soil Testing Initiative (Contd.)

4. Phosphorus Deficiency:

Most samples had low phosphorus levels, ranging from 4.5 to 18 (e.g., Saraswati Devi from Dhamas had 18). Phosphorus is essential for root development and flowering. Farmers were advised to apply rock phosphate or bone meal.

5. Potassium Variation:

Potassium levels varied across samples. For instance, Malti Devi from Dhamas had a high level (632), while Saraswati Devi had a low level (193). As potassium is important for water regulation, disease resistance, and drought tolerance, recommendations included using potassium sulfate or potassium-rich organic compost.

Handholding Support for Credit Linkage

Under the handholding credit initiative by GRASS, multipurpose primary agricultural credit cooperative society (Dhams) facilitated loans for 51 farmers. Additionally:

- 2 farmers received loans under the CCL (Cash Credit Limit) scheme.
- 56 members from 6 SHGs (Self-Help Groups) were linked to bank loans through SHG-bank linkage.
- 41 farmers from 3 SHGs received internal loans from their group savings to bridge access to formal credit.



Success Story

A Transformative Journey in Almora – Millet Farming, Empowered Farmers, and Stronger Communities

In the scenic villages of Dhamas, Raun, and Dal in Almora, a remarkable transformation has taken place in agriculture. Farmers who once struggled with low prices and unstable millet yields are now shaping a new path of success. This transformation was made possible through the NABARD-funded Livelihood and Enterprise Development Programme (LEDP), implemented by the Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS).

A few years ago, farmers sold finger millet (mandua) for a meager ₹10–20 per kg. Today, they sell their produce at ₹60–70 per kg—a dramatic shift that has increased their income and given them hope for a better future. This change began with the introduction of high-yielding millet varieties such as VL-400, VL-379, and VL-376, developed by VPKAS. These varieties not only provided higher yields but also proved ideal for Almora's challenging climate due to their drought tolerance.

The collaboration between farmers, VPKAS, SHGs, and the LEDP program has been deeply inspiring. Under LEDP, 87 farmers participated in seed production and have now become seed suppliers instead of just recipients. This transition strengthened the local agricultural supply chain and created a model for sustainable farming. Raun village, once struggling, is now emerging as a seed production hub and a role model for nearby communities.

But this journey wasn't limited to seed innovation. In Raun, over 30 women farmers began using a millet processing unit established for 150 farmers to empower their community. With support from GRASS and NABARD's training in organic farming and financial literacy, these women started selling finger millet flour in local markets. This increased their supplemental income and improved their standard of living. This initiative is not just about farming—it's about entrepreneurship, self-reliance, and breaking social barriers.



Success Story (Contd.)

The growing demand for millets, driven by their nutritional benefits and popularity as a sustainable crop, has further strengthened farmers' resolve. Under the guidance of GRASS and NABARD, they are expanding production, accessing larger markets, and ensuring their success story inspires others.

This story is not just about farming—it's a testament to the resilience of farmers, the power of community collaboration, and the transformational impact of sustainable agriculture. It is the story of the women of Raun, and the farmers of Dhamas and Dal, who overcame challenges and emerged stronger. It is the result of the collective efforts of VPKAS, SHGs, and GRASS in creating a model of prosperity, self-reliance, and sustainability.

Together, we are not just growing crops—we are growing hope, empowering communities, and building a prosperous future. It is a journey of resilience, cooperation, and unwavering belief.

Conclusion and Way Forward

The Livelihood and Enterprise Development Programme (LEDP) has proven to be a transformative initiative for the farmers of Almora. Through capacity building, financial empowerment, and access to markets, the program has enhanced agricultural productivity and income while empowering women farmers. As a result, the communities in Raun, Dhamas, and Dal are now more resilient, self-reliant, and economically prosperous.

The lessons learned from the program will serve as a blueprint for future rural development initiatives, ensuring that the farmers of Almora continue to thrive. With ongoing support, the program will expand its reach, impact, and sustainability, ensuring that more rural communities across Uttarakhand benefit from this transformative model.



Dosad Watershed Project: A Pathway to Sustainable Land and Water Management

The Dosad Watershed Project, implemented by Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) and supported under NABARD's Watershed Development Fund (WDF), marks a significant step toward ecological restoration and livelihood enhancement in the Dwarahat block of Almora district, Uttarakhand. The project spans 1,642.2 hectares, covering 20 villages and benefiting approximately 760 farming families. The initiative was officially approved on 14 February 2024.

The Dosad region, located on the southern ridge of the Kumaon Hills, faces multiple challenges including water scarcity, land degradation, and limited irrigation, which have traditionally hindered agricultural productivity. Despite this, the area possesses high potential for agriculture-based livelihoods, particularly for spices and vegetables, owing to its favorable climate, topography, and road connectivity to major markets like Almora, Ranikhet, and Haldwani.

Recognizing the urgency and opportunity, NABARD selected GRASS—as the Project Implementing Agency (PIA). GRASS has previously partnered with NABARD on social and environmental initiatives and is well-positioned to lead community-driven development in this fragile ecosystem.

Community Participation and Mobilization

To ensure strong local ownership, GRASS conducted village-level meetings across all 12 core villages—Bargal, Bhandargaon, Chabbisa, Chilalgaon, Masar, Melta, Nehragunth, Sakuni, Sailisunoli, Satinaugaon, Syalsuna, and Ubyari.

Objectives

- Introduce soil and water conservation structures to reduce erosion and runoff
- Improve soil fertility and increase agricultural productivity
- Promote crop diversification, intercropping, and climate-resilient farming practices
- Enhance groundwater recharge through water conservation techniques
- Build the capacity of Gram Panchayats for effective watershed management
- Strengthen local value chains in agriculture and horticulture
- Engage landless and vulnerable families in income-generating activities
- Support sustainable land and water management for climate change adaptation



Community Participation and Mobilization (Contd.)

The project team:

- Explained the programme and its long-term benefits to the villagers.
- Obtained formal consent from Gram Pradhans and Van Panchayat Sarpanchs.
- Encouraged and received voluntary labor (Shramdaan) from community members.
- Promoted the reduction of open grazing during the preparatory phase.

These efforts helped complete the Pre-Capacity Building Phase (Pre-CBP) and laid the foundation for full community involvement in the implementation phase.

Implementation Plan and Activities

The project is being implemented over 1,000 hectares, combining forest and non-forest lands. The initial phase focuses on 100 hectares selected for the Capacity Building Phase (CBP), with core activities including:

- Building farm bunds and check dams.
- Constructing earthen pit tanks for rainwater harvesting.
- Enhancing agricultural land under Forest Panchayats.
- Supporting crop diversification and agroforestry.
- Livelihood promotion for landless families.

A local 11-member Watershed Committee has been formed in Masar to lead coordination, monitor progress, and ensure community participation.

Pre-CBP Activities: Community Mobilization through Shramdaan

A 4-day Shramdaan campaign engaged community members in essential preparatory tasks focused on water conservation and sanitation. Activities included:

1. Hand Pump Area Cleaning – Chilal Gaon

- Cleared debris and vegetation.
- Improved drainage to prevent stagnation.

2. Village Pathway to Hand Pump – Chilal Gaon

- Leveled and cleared the pathway.
- Enhanced accessibility and hygiene.

3. Drainage Line Cleaning – Kulludar Area

- Removed silt and blockages.
- Repaired sections to restore flow.

4. Naula Rejuvenation in Kaptoi Tok, Masar & Chhabisa

- Removed silt, debris, and garbage.
- Improved inflow/outflow channels.

Exposure Visit

On 15 March 2024, 20 farmers visited Daspad village in Dhauladevi block, Almora to observe integrated watershed development in action. Key learnings included:

- Importance of participatory implementation.
- Exposure to sustainable land and water practices.
- Insights into replicable livelihood models.

Capacity Building Phase (CBP) Planning

Following Pre-CBP, a Detailed Project Report (DPR) was prepared with community input for three villages: Chhabisa, Chilal Gaon, and Masar, covering 116.68 hectares (100.92 hectares treatable).

CBP components include:

- Land use planning with conservation structures.
- Livelihood promotion tailored to socio-economic realities.
- Integrated farming and climate-resilient techniques.

This structured approach ensures sustainability and livelihood security for farming communities in the fragile Dosad watershed.

Targeted Intervention Project

Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) has been implementing the Targeted Intervention (TI) Project in Almora since 2010, with support from the Uttarakhand State AIDS Control Society. The project aims to prevent the spread of HIV/AIDS and protect communities from sexually transmitted infections (STIs), especially in rural and high-risk areas.

Project Reach and Expansion

This year, GRASS worked with 400 individuals from High-Risk Groups (HRGs) – including 250 in Almora and 150 in Ranikhet. Through surveys and mapping, we identified areas with the highest risk and focused our efforts there.

Reaching Migrant Workers

From 2022 to 2025, we reached out to 15,137 migrant workers (including Nepali and Bihari migrants) through awareness drives, street plays, group meetings, and health camps. We ensured they received timely information and services related to HIV prevention and care.

In April 2024 and January 2025, two individuals tested HIV-positive. Both were linked to Sushila Tiwari Hospital, Haldwani for free treatment and counseling.

Empowering Women Through Health Education

We focus strongly on women's health, educating them about:

- Safe sex and how HIV spreads
- Risks from infected blood or needles
- How to prevent mother-to-child transmission of HIV

Key Components of the TI Project

Our regular activities under the Targeted Intervention programme include:

- Behavior Change Communication (BCC)
- Condom promotion
- STI Management
- Creating a supportive environment
- Community mobilization
- Referral and linkages



Strengthening Implementation Under NACP Phase V (2021–26)

All our interventions align with the goals of NACP Phase V, which aims to:

- Reduce new HIV infections and AIDS-related deaths by 80% (from 2010 baseline)
- Eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis
- Promote universal access to quality STI/RTI services
- End stigma and discrimination

Specific Objectives Under NACP Phase V:

- 95% of people living with HIV should know their status
- 95% of those diagnosed should receive treatment
- 95% of those on treatment should achieve viral suppression
- 95% of pregnant and breastfeeding women living with HIV should have suppressed viral load
- Less than 10% of PLHIV and key populations should face stigma or discrimination

Monthly Health Camps (2024–25)

We organized 15 monthly health camps led by doctors to bring healthcare to the community. Each camp offered:

- Free screening and consultation for HIV/STIs
- Distribution of medicines, condoms, and IEC materials
- Support to address stigma, travel issues, and cost barriers

These camps helped in early diagnosis, prevention, and trust-building within the community.

World AIDS Day 2024

Theme: Let Communities Lead: My Health, My Right

To mark World AIDS Day on December 1, 2024, GRASS organized an awareness rally at the Nursing College in Almora, in collaboration with local health authorities and students.

The rally was flagged off by Dr. R.C. Pant, Chief Medical Officer (CMO) of Almora. In his address, he highlighted the importance of community-led efforts in fighting HIV/AIDS, encouraged people to break stigma, and emphasized the need for early testing and prevention.

Students from the college actively participated by distributing IEC materials, engaging with the public, and spreading awareness about HIV transmission, prevention, and available treatment services.

This event reinforced the message that health is a human right, and empowered local communities to take an active role in promoting public health.

Biannual Community Awareness Events

In 2024–25, GRASS organized two major community awareness events to engage and educate high-risk groups. These events were designed to be interactive and inclusive, helping participants learn in a fun and safe environment.

Key Highlights:

- Games and Quizzes made learning about HIV/STIs enjoyable and easy to understand.

Monitoring PCPNDT Act Compliance

GRASS is an active member of the district-level committee that monitors compliance with the PCPNDT Act, which aims to prevent female foeticide and ban sex-selective practices.

Every quarter, the committee inspects ultrasound clinics to check records, licenses, and ensure there is no misuse for sex determination. Recent inspections found minor issues like incomplete documentation but no confirmed cases of illegal sex determination. Non-compliant clinics received warnings and guidance.

Challenges like hidden practices and underreporting remain. To address these, GRASS conducts awareness campaigns and training sessions for healthcare providers.

These efforts promote ethical healthcare, gender equality, and protect the rights of unborn girls.

Special Awareness Session at Nari-Niketan

In March 2025, GRASS held a dedicated health awareness session for women at Nari-Niketan, Almora.

Key Highlights:

- Women were educated about HIV and STIs, including causes, prevention, and treatment.
- One woman tested positive for syphilis during screening and was immediately referred for medical care.
- The team provided counseling and follow-up support to ensure proper treatment and care.

This session helped raise awareness and strengthened healthcare access for vulnerable women.

Key Highlights (Contd.)

- Open Q&A sessions with peer educators encouraged honest conversations and helped clear doubts.
- Prize distribution boosted community participation and made the events more engaging.
- The events helped build trust, community bonding, and health awareness among participants.

Community-Based Field Interventions Under NACP Phase V

GRASS carried out the following field-level activities to meet the objectives of the national program:

- **Street plays (Nukkad Natak):** Performed in public spaces to raise awareness among migrants and the general population.
- **Drop-In Centre (DIC):** Provided a safe, accessible space for migrants and Female Sex Workers (FSWs) to receive counseling, testing, and health information.
- **Monthly follow-ups with PLHIV:** Regular phone or in-person contact to track treatment adherence and health status.
- **Group meetings:** Conducted with migrant workers and FSWs to discuss safe practices, STI prevention, and available services.
- **Community-Based Screening (CBS):** Focused on individuals who had never been tested or had limited access to healthcare.
- **Community events with prizes:** Held to increase awareness and encourage active participation.
- **TB screening:** Integrated into health camps for early detection and timely referral.



Success Story

Hope in the Hills: Empowering Communities in Almora through Strength and Support

In the serene mountain villages of Almora, where tradition runs deep and life moves at a gentle pace, sensitive topics like HIV have long been shrouded in silence. Fear and stigma have kept many from seeking the support they need. Yet, beneath this quiet exterior, a profound transformation is taking place.

With the invaluable support of the Uttarakhand State AIDS Control Society, the dedicated team of GRASS, has been unwavering in its mission to reach marginalized and vulnerable groups—including migrants, daily wage workers, and women facing challenging circumstances—bringing vital health education and care to those often overlooked.

Building Trust One Step at a Time

Each month, the outreach team meticulously plans their visits, identifying villages and individuals at risk, especially those hesitant to come forward. Navigating steep hills and difficult terrain, the team demonstrates exceptional commitment, patiently engaging communities because they understand that trust is earned, not demanded.

“We don’t just talk about HIV; we listen first,” explains a team member.

“Once people feel safe, they begin to open up.”

From Fear to Courage: Personal Stories of Transformation

In April 2024, during a routine outreach session, the team encountered a woman quietly struggling with health concerns. Upon conducting a health check, she was diagnosed HIV positive. Fearful—not of the disease but of societal judgment—she found reassurance through continuous counseling and support. The team accompanied her to the ART Center at Sushila Tiwari Hospital, Haldwani, ensuring she accessed the treatment and care essential for her well-being.

Similarly, in January 2025, a young migrant laborer from Bihar, unaware of HIV risks, was diagnosed during a community screening. Initially shocked, he soon received compassionate guidance from the team, helping him confront his fears and begin treatment with confidence.

“I thought I was healthy. No one had ever talked to me about HIV before,” he reflected.



Success Story (Contd.)

Gaining Acceptance in Conservative Communities

In close-knit mountain communities, outsiders are often met with suspicion, particularly when discussing sensitive health topics. Initial resistance was common—contractors denied access to workers, and some villagers dismissed the efforts as unnecessary. However, through persistent engagement, respectful dialogue, and communication in the local language, the team has gradually won hearts and minds.

“At first, doors were closed. Now, people invite us in for tea,” shares a staff member with a smile.

As trust deepens, community members increasingly participate in group meetings, health checkups, and open conversations about HIV prevention and care.

Combating Stigma through Knowledge and Compassion

Testing positive for HIV can be daunting, often accompanied by fears of rejection and isolation. Through empathetic counseling and free access to Anti-Retroviral Therapy (ART), many have reclaimed their health and hope.

“Initially, the medication caused side effects, and I almost gave up. But my counselor encouraged me to stay strong—and now I feel healthy and hopeful,” shares a woman beneficiary.

Extensive Community Reach and Impact

Since the project’s inception, thousands have been reached through a comprehensive array of activities, including:

- Health education talks and interactive group meetings
- Distribution of protective materials
- Confidential one-on-one counseling sessions
- Community-based health screenings every six months

“HIV is not a curse; it’s a medical condition. With proper treatment, people can live full, healthy lives,” affirms a community health worker.

A Message of Hope from the Hills

“Though we live far from the cities, we deserve equal care and dignity,” says a local community leader.

“Thanks to this project, we are no longer in the dark.”

This initiative transcends healthcare—it is a movement rooted in respect, awareness, and collective care. Where silence once reigned, dialogue now flourishes; where fear existed, understanding has taken root; and where isolation prevailed, solidarity thrives.

Together, We Rise

As the journey continues across these hills—both physical and emotional—the commitment remains unwavering: no one in Uttarakhand’s remotest communities should be left behind. With compassion, knowledge, and persistence, transformative change is not just possible—it is happening.